सीएम योगी ने पीएम आवास योजना लाभार्थियों के खातों में 500 करोड़ ट्रांसफर किए

शहरी विकास के लिए दी 3800 करोड़ की योजनाओं की सौगात

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शहरी विकास के लिए 3800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम आवास योजना शहरी में 58,903 लाभार्थियों के खातों में 500 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। प्रदेश के 651 नगर निकायों में 1000 फ्री वाई-फाई जोन की शुरुआत की। प्रदेश के सात शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसों व सात इलेक्ट्रिक बस डिपो की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन की लगभग 909 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन की 627 करोड़ की 28 सॉलिड वेस्ट प्लांट, 13 लिगेसी वेस्ट रेमिडिएशन, आगरा में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और 1100 सुलभ व पिंक शौचालय का शिलान्यास किया। अमृत मिशन व राज्य सेक्टर की 926 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। नगर निगम अयोध्या व मथुरा-वृंदावन के कार्यालय भवन शिलान्यास व नगर निगम गाजियाबाद की 606 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कूड़े के जैविक प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, नगर निगम कानपुर और जर्मन एजेंसी जीआईजेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे व जीआईजेड की प्रोजेक्ट हेड वैशाली नंदन ने एमओयू का आदान-प्रदान किया।

सीएम ने मंगलवार को कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों में सफाई दिखाई पड़ती है। मार्च 2017 की स्वच्छता रैंकिंग में गोंडा जिला देश में सबसे नीचे था। आज भारत के टॉप 10 शहरों में राज्य के पांच नगर शामिल हैं। इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से बेहतरीन सुविधा है। मेट्रो से पहले शहरों में इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जा रही है। लखनऊ, गोरखपुर, काशी में इलेक्ट्रिक बस की सुविधा शुरू की जा चुकी है। मंगलवार से सात शहरों मेरठ, आगरा, मथुरा-वृन्दावन, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद में इलेक्ट्रिक बस सेवा व इलेक्ट्रिक बस डिपो की सुविधा शुरू की गई है।

07 शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ

651 निकायों में एक हजार फ्री वाई फाई जोन शुरू

नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना टैक्स देना चाहता है। टैक्स को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था से जोड़ने से नगर निकाय की आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से नगर निकाय नगरीय क्षेत्र के लिए और बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के नगर निकाय इस दिशा में रुचि लेकर केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ लागू करने का काम करेंगे। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास पथ पर बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बना रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में 8.28 लाख लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 7.23 लाख लाभार्थियों को यह प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हर स्ट्रीट वेंडर को एक बोर्ड दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री 210 प्रवक्ताओं व शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे

राज्य मुख्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ जनवरी को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में 210 नवनियुक्त प्रवक्ता और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में लोकसेवा आयोग के माध्यम से 2018 में 10768 सहायक अध्यापक पदों पर भर्तियां शुरू की गई थीं। चौथे चरण में 140 सहायक अध्यापकों व 70 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

आज सामाजिक पेंशन की धनराशि जारी करेंगे

राज्य मुख्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वृद्धावस्था, विधवा-निराश्रित, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही जनवरी, फरवरी व मार्च की पेंशन राशि जारी करेंगे। इस आखिरी तिमाही की किस्त से लाभार्थियों को बढ़ी पेंशन राशि मिलने की शुरुआत होगी। सीएम के बटन दबाते ही लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि का हस्तांतरण शुरू हो जाएगा।